

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 310/VII-A-1/2023/08(ख)/2016
देहरादून, दिनांक: 23 फरवरी, 2023

अधिसूचना सं० 292/VII-A-1/2023/08(ख)/2016 दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव- मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी (मा० विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 292/VII-A-1/2023-08(ख)/2016
देहरादून: दिनांक: 22 फरवरी, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम-4 के उपनियम (3) व उपनियम (6)(क), नियम-10(2) एवं नियम-15 में अग्रेतर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, -

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (संशोधन) नियमावली, 2023

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) यह सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगी।

- नियम 4 का संशोधन 2. मूल नियमावली के नियम 4(3) एवं (6)(क) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ -1

विद्यमान नियम

- न्यास का गठन एवं प्रबन्ध 4.(3) (3) शासी परिषद में निम्नलिखित होंगे :-

(क)	सम्बन्धित जनपद के मा0 अध्यक्ष प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित मा0 सदस्यगण विधान सभा	सदस्य
(ग)	जिलाधिकारी/कलेक्टर	सदस्य
(घ)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हो)	सदस्य
(ङ)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(च)	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
(छ)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ज)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(झ)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ञ)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी	सदस्य

स्तम्भ -2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 4.(3) शासी परिषद में निम्नलिखित होंगे :-

(क)	जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित मा0 सदस्यगण लोकसभा	सदस्य
(ग)	संबंधित मा0 सदस्यगण राज्यसभा	सदस्य
(घ)	संबंधित मा0 सदस्यगण विधान सभा	सदस्य
(ङ)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हो)	सदस्य
(च)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(छ)	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
(ज)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(झ)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ञ)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ट)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी	सदस्य

	अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ठ)	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ड)	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(ण)	अधिकांशी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(त)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(थ)	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट :- संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परिषद के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा।

	अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	
(ठ)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ड)	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ण)	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(त)	अधिकांशी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(थ)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(द)	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट :- 1- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कलेक्टर के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शासी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

2- मा० सदस्य लोकसभा उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के शासी परिषद के सदस्य होंगे।

3- मा० सांसद राज्यसभा द्वारा चुने गए एक जिले की शासी परिषद के सदस्य होंगे। (राज्यसभा सांसद अपने द्वारा चुने गए जिले का नाम राज्य के सचिव खनन को सूचित करेंगे जो संबंधित जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कलेक्टर को सूचित करेंगे।)

4- जनपद के अन्तर्गत मा० विधान सभा के सदस्यगण शासी परिषद के सदस्य होंगे।

(6)(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(एक)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(तीन)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(चार)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(पांच)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिकांशी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(छः)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिकांशी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(सात)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिकांशी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य

(6)(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(एक)	जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(तीन)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(चार)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(पांच)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिकांशी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(छः)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिकांशी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(सात)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिकांशी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य

	निम्न स्तर का न हो)	
(आठ)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
नौ	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
दस	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
ग्यारह	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
बारह	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग)	सदस्य
तेहरा	ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी	सदस्य सचिव

(आठ)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
नौ	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
दस	जिला राज्य पंचायत अधिकारी	सदस्य
ग्यारह	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
बारह	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग)	सदस्य
तेहरा	ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नियम 10 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

न्यास निधि हेतु 10.(2) अंशदान

गौण खनिजों के मामले में:-

1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक रायल्टी का 25 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।
2. ईट भट्टा समाधान रायल्टी का 15 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा की जायेगी।
3. उपखनिजों (बालू, बजरी, बोल्टर, सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड आदि) के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
4. सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी, बोल्टर पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
5. जल विद्युत परियोजना में उपखनिज उपयोग किये जाने पर उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10.(2)

गौण खनिजों के मामले में:-

1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक रायल्टी का 15 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।
2. ईट भट्टा समाधान रायल्टी का 10 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा की जायेगी।
3. उपखनिजों (बालू, बजरी, बोल्टर, सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड आदि) के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
4. सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी, बोल्टर पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
5. जल विद्युत परियोजना में उपखनिज उपयोग किये जाने पर उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

6. नहर/जलाशय सफाई/खुदान से प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली धनराशि की रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

6. नहर/जलाशय सफाई/खुदान से प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली धनराशि की रायल्टी का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

नियम 15 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नियम 15 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

न्यास निधि का संचालन

15.

न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा।

15.

15(क)

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

न्यास निधि, न्यास के नाम से पब्लिक सैक्टर बैंक अथवा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंकों को छोड़कर) में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा।

न्यास निधि, न्यास के नाम से पब्लिक सैक्टर बैंक अथवा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंकों को छोड़कर) के बचत खाते में रखी जायेगी परन्तु न्यास निधि के बचत खाते से भिन्न खातों को बचत खाते में आगामी 6 माह में परिवर्तित किया जाना होगा।

आज्ञा से,



(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव